



अग्रभारत

नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्ष: 19

अंक: 103

आगरा, बुधवार 30 सितम्बर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 रू.

केजरीवाल का दावा: 12 सालों में सबसे ज्यादा मोदी के भाई ने कमाया

नई दिल्ली(ए)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी भाई-भतीजावाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं और उनकी सरकार ने पिछले 12 सालों में देश को पूरी तरह से लूट लिया है। केजरीवाल ने कहा कि जब मोदी सत्ता में आए थे, तब लोगों को एक फ्रेश चेहरा और फ्रेश एनर्जी की उम्मीद थी। लोगों को लगा था कि वह कुछ करेंगे, देश बदल देंगे और भाई-भतीजावाद खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके ना आगे कोई, ना पीछे कोई था। हालांकि, केजरीवाल ने दावा किया कि आज सबसे ज्यादा भाई-भतीजावाद का उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का एक भाई है जिसका नाम अछानी है, जिसने पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है।



इसी तरह, उनका एक भतीजा जय शाह है, जिसने इस अवधि में सबसे ज्यादा तरक्की की है। केजरीवाल के अनुसार, यह इतिहास में भाई-भतीजावाद की सबसे बड़ी मिसाल है। आप सुप्रीमो ने सवाल उठाया कि इन 12 सालों में लोगों को क्या मिला?

कुछ नहीं मिला। उन्होंने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाया, खासकर तब जब पैसे या अन्य कारणों से पार्टियां बदलने वाले विधायकों को चाणक्य कहा जाता है। केजरीवाल ने चाणक्य शब्द के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई और कहा

कि असली चाणक्य राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में 120 विधायक खरीदे-बेचे गए हैं। केजरीवाल ने इसे गद्दारी करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकारें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और पैसों के दम पर तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें करने वाले लोग देशद्रोही हैं, चाणक्य नहीं। केजरीवाल ने अपने निजी करियर का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे वह इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर की नौकरी छोड़कर 10 साल तक झुगियाँ में रहे। उन्होंने कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा देश के लिए रही है और अगर लोकपाल बिल बन जाता तो उन्हें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।

उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट की सराहना की जिसमें आज के माहौल में इनके खिलाफ कुछ बोलना सुसाइडल है जैसी हिम्मत दिखाई गई।

मेरठ-सहारनपुर के बाद अब मथुरा का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष

लखनऊ,(ए)। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने संगठन को क्षेत्रवार मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। मेरठ-सहारनपुर दौरे के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के संभावित रूप से मथुरा में दो दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक यह दौरा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है, हालांकि कार्यक्रम की अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में दो-दिवसीय प्रवास के जरिए संगठन और चुनावी तैयारियों की जमीनी स्थिति जानने का क्रम शुरू किया है। मेरठ और सहारनपुर के बाद अब ब्रज क्षेत्र के मथुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान उनके प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ और संगठनमंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मथुरा में दो दिवसीय प्रवास के दौरान नितिन नबीन स्थानीय सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे। इसके अलावा बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक संगठन की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलने वाली प्रतिक्रिया को भी बैठक में अहमियत दी जाएगी।

बीजेपी नेतृत्व का फोकस केवल चुनावी रणनीति बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन की जमीनी मजबूती और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बेहतर करने पर भी है। इसी क्रम में नबीन अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। इससे पहले नितिन नबीन ने 21 और 22 सितंबर को मेरठ और सहारनपुर का दो दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया था। सहारनपुर में उन्होंने पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। पश्चिमी यूपी के बाद मथुरा में संभावित दो दिवसीय प्रवास को भी इसी संगठनात्मक अभियान की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का जोर विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के सभी स्तरों को सक्रिय करने और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने पर है।

ममता ने बढ़ाया पुराने विरोधियों की ओर दोस्ती का हाथ

कोलकाता(ए)। चुनाव आयोग को लेकर सामने आई हालिया रिपोर्ट ने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के सामने आते ही सत्ताधारी भाजपा पर विपक्ष ने ज़ोरफ़ा हमला बोल दिया है। सभी विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, जिससे देश का सियासी पारा गरमा गया है।इसी गहगमहमी के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पुराने और कड़े प्रतिद्वंद्वी वामपंथी दल से मेल-मिलाप के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने खुद माकपा के महासचिव को फोन कर इस मुद्दे पर चर्चा की है। हालांकि, सीपीआई(एम) इस पेशकश पर फिलहाल फूंक-फूंक कर कदम रखती नजर आ रही है।

यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने ही 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को सत्ता से बेदखल कर मुख्यमंत्री का पद संभाला था। दशकों तक वामदल के खिलाफ संघर्षरत रहीं ममता के लिए यह कदम बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। मौजूदा परिस्थितियों में, जब विपक्षी दल एक होकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे हैं, ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए व्यापक एकजुटता की तलाश में पुराने समीकरणों को साधती दिख रही हैं। दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग और आगे की रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ-साथ सीपीआई(एम) के महासचिव एम.ए. बेबी से भी फोन पर अलग-अलग बातचीत की है। यही नहीं, हाल ही में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने खुलकर कहा था कि अब यह देखने की जरूरत नहीं है कि कौन नीला है या कौन लाल। उन्होंने अपने बयान में कहा था, पूरा देश एकजुट है। हम मिलकर लड़ेंगे और यह देखने की जरूरत नहीं है कि कौन लाल, कौन नीला और कौन पीला। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। यह बयान विपक्ष की व्यापक एकजुटता की ओर इशारा करता है, जहां साझा दुश्मन के खिलाफ पुराने राजनीतिक मतभेदों को भुलाने की कोशिश की जा रही है। वामपंथी दल की प्रतिक्रिया भविष्य की राजनीतिक दिशा पर काफी हद तक निर्भर करेगी।

कुशीनगर(ए)। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार देर रात नारायणी नदी ने तबाही मचा दी। तमकुहीराज तहसील के ततवा टोला स्थित एपी टटबंध टूट गया, जिससे पानी तेजी से गांवों में घुस गया। इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जबकि लगभग दो दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडा रहा है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, यह

लोग प्रभावित हुए हैं। टटबंध टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी आनन-फानन में मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पहले ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों को

और व्यापक स्तर पर बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संजीव यादव नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि टटबंध करीब तीन दिन से धीरे-धीरे कट रहा था और उसमें सीपेज हो रहा था, लेकिन इसे बंद करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कटाव शुरू होने पर अधिकारी मौके से भागने लगे और बाद में डीएम-एसपी के आने पर ही बाकी लोग वहां पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार,

बाढ़ प्रभावित लोग तटबंधों या अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण लिए हुए हैं, लेकिन खाने-पीने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बाढ़ से सामान के नुकसान की भी बात कही है। फिलहाल, प्रशासन की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित निकालना और टटबंध टूटने से प्रभावित इलाकों में राहत-बचाव कार्य को तेज करना है। मुख्यमंत्री लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं।

सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात ही घटना का संज्ञान लिया और गोरखपुर मंडलायुक्त, एडीजी तथा कुशीनगर के जिलाधिकारी से तत्काल पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत-बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी सक्रिय कर मौके पर पहुंचने



सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात ही घटना का संज्ञान लिया और गोरखपुर मंडलायुक्त, एडीजी तथा कुशीनगर के जिलाधिकारी से तत्काल पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत-बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी सक्रिय कर मौके पर पहुंचने

कांग्रेस ने ममता को दिया झटका, एकसाथ 100 नेता तोड़े

कोलकाता(ए)। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को एक और बड़ा झटका लगा है। 100 से अधिक टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यह राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुआ है, जब राज्य में दो बड़ी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। गौरतलब है कि बनर्जी गुट पहले ही पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिह्न जोड़ा फूल खो चुका है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें फ्रीज कर दिया है, जिससे पार्टी की पहचान पर गहरा संकट मंडरा रहा है।मालदा के महीष बाथानी क्षेत्र में रविवार को तृणमूल कांग्रेस के कई सदस्यों ने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई। इनमें 13 पंचायत सदस्य, एक पंचायत समिति सदस्य, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष और 100 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं। इस बड़े दल-बदल को लेकर बलरामपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला

कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बी हल्दर जैसे कई

वजह बताते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में एक क्षेत्रीय दल होने के नाते तृणमूल का भाजपा के खिलाफ लड़ना संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भाजपा से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ आए हैं। इस बीच, बंगाल में 6 अक्टूबर को दो महत्वपूर्ण सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनके परिणाम 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इन सीटों में से एक नंदीग्राम है, जो शुभेंदु अधिकारी के सीट छोड़ने के बाद खाली हुई है।

दूसरी सीट रेजीनगर है। यह सीट तब खाली हुई थी जब आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर ने नौदा सीट बरकरार रखी थी। रेजीनगर से अब हुमायूं कबीर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ममता गुट ने रबीउल आलम चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह दल-बदल इन उपचुनावों से ठीक पहले हुआ है, जो राज्य की राजनीतिक तस्वीर पर निश्चित रूप से असर डालेगा।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जिस महीष बाथानी क्षेत्र में यह टूट हुई है, उसे कभी कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता था। हालांकि, ममता बनर्जी का राजनीतिक कद बढ़ने के बाद यहां की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया था। अब इस दल-बदल के जरिए कांग्रेस अपनी पुरानी पकड़ को दोबारा मजबूत करने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस में शामिल हुए शराफत अली ने तृणमूल छोड़कर जाने की



ऐतिहासिक शाही मस्जिद पर सड़क की चोट, तनाव और कानूनी लड़ाई



उज्जैन (ए)। उज्जैन के अब्दालपुर इलाके में मौजूद ऐतिहासिक शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हटाने को लेकर तनाव फैल गया है। सोमवार को हुई प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में लोकल निवासियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुईं, जिसके बाद पथराव और आंसू गैस के गोले दोगे गए। यह विवाद केवल प्रशासन और लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर भी इस लेकर दो अलग-अलग राय सामने आई हैं और मामला अब इंदौर हाईकोर्ट पहुंच गया है। करीब 630 साल पुरानी यह इमारत 14वीं शताब्दी के अंत में, मालवा के पहले स्वतंत्र शासक दिलावर खान गोरी के शासनकाल (1390-1404 ईस्वी) में निर्मित हुईं मशीनों के साथ मस्जिद के प्रभावित का दावा है कि यह उज्जैन की पुरानी स्थापत्य कला और मध्यकालीन सल्तनत

कालीन वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो सदियों से कंठल के व्यस्त व्यापारिक मार्ग पर इस इलाके की पहचान बनी हुई है। मस्जिद की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व को साबित करने के लिए 1925 का सिंधिया रियासत के ग्वालियर राज्य के टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी एक पत्र और 1985 के मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जैसे शासकीय दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है, जिनमें इसके अस्तित्व और कुल क्षेत्रफल का विस्तृत ब्यौरा दर्ज है। मौजूदा विवाद उज्जैन में कंठल से गोपाल मंदिर मार्ग पर जारी मशीनों के साथ मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को भी इलाके में

तनाव बना रहा और पुलिस के साथ झड़प के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना पर मुस्लिम समाज के भीतर भी मतभेद उभरकर सामने आए हैं, एक धड़ा शहर के विकास और चौड़ीकरण के काम को लेकर संरचना के संबंधित भाग को हटाने के पक्ष में है, जबकि दूसरा पक्ष इसकी ऐतिहासिकता और अदालत के फैसले का हवाला देकर पूरी तरह से तोड़ने का विरोध कर रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई और विरोध के बीच, पूरा मामला अब इंदौर उच्च न्यायालय पहुंच गया है, जहां कानूनी प्रक्रिया जारी है। अदालत का फैसला ही इस जटिल विवाद का अगला मोड़ तय करेगा, लेकिन फिलहाल उज्जैन के अब्दालपुर इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, और प्रशासन तथा स्थानीय समुदाय दोनों ही आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।